

कौशांबी संदेश

खबर संक्षेप

वृद्धजनों की सेवा करना बहुत ही पुण्य का कार्य : एडीएम

अखंड भारत संदेश

अन्तर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर वृद्धाश्रम ओसा में कार्यक्रम का आयोजन वृद्धजनों को किया गया सम्मानित



वृद्धजनों को सम्मानित करते एडीएम
अधिकारी सुधीर कुमार, वृद्धाश्रम संचालक आलोक राय एडीओ

पंचायत कमलाकांत व अन्य कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

कौशांबी। अन्तर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर वृद्धाश्रम, ओसा में वृद्धजन सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। अपर जिलाधिकारी जयचन्द्र पाण्डेय द्वारा वृद्धजनों को वस्त्र एवं फल वितरण किया गया तथा वृद्धजनों को शाल ओढ़कर उनसे आशीर्वाद भी प्राप्त किया गया।

अपर जिलाधिकारी ने कहा कि वृद्धजन हमारे घोर हैं। इनकी सेवा करना बहुत ही पुण्य का कार्य है। उनके द्वारा वृद्धजनों से वृद्धाश्रम की व्यवस्थाओं के विषय में भी विस्तृत जानकारी प्राप्त करने पर वृद्धाश्रम करने एवं स्कूल की दीवार पर पट्टिकाले वृद्धजन करने व वृद्धाश्रम ही अब एक मात्र हम लोगों का सहारा है। यहां पर प्रतिदिन समय-समय पर मीनू के अन्यसार नाशरा एवं औजन उपलब्ध कराया जाता है। यहां पर विविध समय-समय पर मीनू के अन्यसार नाशरा एवं औजन की कार्यक्रम से अपने गांवों में वृद्धियों की वृद्धि एवं वृद्धियों की वृद्धि करने के बहर व्यवस्था सुनिश्चित करने की निर्देश दिये।

सम्पादकीय

दुविधा में फंसी कांग्रेस

पांच महीने बाद जिस राज्य में चुनाव होने वाले हों, वहां सत्तारूढ़ दल के अंदर इस तरह की अनिश्चितता पार्टी नेतृत्व की घोर असफलता ही कही जाएगी। हालांकि लंबे समय से कुछ न करने का आरोप झेलने वाले कांग्रेस नेतृत्व ने पिछले दिनों कुछ ठोस फैसले लेकर पॉजिटिव संदेश दिया था। पंजाब में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चननी और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच गुरुवार को हुई लंबी बैठक भी कोई नतीजा नहीं दे सकी। वैसे विवाद सुलटाने की कोशिश अभी जारी है लेकिन हकीकत यही है कि पंजाब में कांग्रेस अपनी ही बनाई गृथी में कुछ इस तरह उलझ गई है कि उससे निकलते नहीं बन रहा। नए मुख्यमंत्री चननी के फैसले पर प्रदेश पार्टी अध्यक्ष सिद्धू ने जिस तरह से प्रतिक्रिया दी, उसके बाद यह समझना मुश्किल है कि कैसे दोनों आपस में तालमेल बनाकर चलेंगे और उसे उस्लों पर समझौता नहीं मानेंगे। उधर, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह तो साफ कर दिया कि वह बीजेपी में शामिल नहीं हो रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही पार्टी छोड़ने का इरादा भी जाहिर कर दिया। उन्हें मनाने की कवायद चल रही है, पर तय नहीं है कि ऊंट आखिरकार किस करवट बैठेगा। पांच महीने बाद जिस राज्य में चुनाव होने वाले हों, वहां सत्तारूढ़ दल के अंदर इस तरह की अनिश्चितता पार्टी नेतृत्व की घोर असफलता ही कही जाएगी। हालांकि लंबे समय से कुछ न करने का आरोप झेलने वाले कांग्रेस नेतृत्व ने पिछले दिनों कुछ ठोस फैसले लेकर पॉजिटिव संदेश दिया था।

पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के विरोध के बावजूद सिद्धु को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाना, अच्छी-खासी दलित आबादी वाले राज्य को पहला दलित सीएम देना और कन्हैया कुमार, जिगन्श मेवानी के रूप में मास अपील वाले युवा नेताओं को प्रवेश देना ऐसे फैसले हैं, जिनके पक्ष-विपक्ष में बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन इसमें संदेह नहीं कि ये खास सोच के साथ लिए गए ठोस फैसले हैं। मगर खास सोच के साथ लिए जाने वाले फैसलों का भी फायदा तभी मिलता है, जब उसे पूरी तैयारी के साथ और उपयुक्त ढंग से लाग किया जाए। कम से कम पंजाब के मामले में इसकी इतनी कमी रही कि घोषणा के बाद से ही इन फैसलों के साइड इफेक्ट नेगेटिव रूप में सामने आने लगे। पिछले दो महीनों के दौरान सिद्धु ने जिस तरह का व्यवहार किया है, उसका बचाव करना उनके समर्थकों के लिए भी मुश्किल है। जाहिर है, यह सवाल उठेगा कि राज्य में पार्टी का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी सौंपने से पहले उनकी काबिलियत परखने का कौन सा तरीका पार्टी हाईकमान ने अपनाया था। गुलाम नबी आजाद और कपिल सिंहल जैसे वरिष्ठ नेताओं ने जो कुछ कहा है, उसके पीछे इन सगालों से पउजी बेचैनी महसूस की जा सकती है। इस बेचैनी को नजरअंदाज करना या इसे पार्टी विरोधी गतिविधियों की श्रेणी में डालने की कोशिश करना आत्मघाती होगा। देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी खुद को एक पूर्णकालिक, जिम्मेदार और पारदर्शी नेतृत्व से वर्चित नहीं रख सकती। पार्टी के सामने चुनौतियां तो अलग-अलग तरह की आती रहेंगी, फैसले भी कुछ सही और कुछ गलत होते रहेंगे, लेकिन सर्वीच्च स्तर पर नेतृत्वहीनता की स्थिति पार्टी को कहीं का नहीं छोड़ेगी।

विपक्षी एकता कहीं ख्याली पुलाव तो नहीं

नरेंद्र नाथ

पिछले कुछ महीनों से 2024 आम चुनावों में बीजेपी से मुकाबले के लिए विपक्षी दलों की एकता की कोशिश चल रही थी। इसके लिए एक के बाद एक कई मीटिंग भी हुई। ऐसा संदेश गया कि विपक्षी दल पिछली गलतियों से सीख लेते हुए इस बार एक मंच पर आएंगे और अपसी मतभेद दूर करेंगे। लेकिन अभी विपक्षी एकता कोई आकार लेती कि पिछली बार की तरह ही फिर यह पटरी से उत्तरती दिखने लगी। हालांकि इस बार इसके पीछे कारण थोड़े अलग हैं। अभी तक विपक्षी एकता में नेतृत्व को लेकर सबसे अधिक विवाद होता था। लेकिन इस बार विपक्षी दलों की आपस में ही सेंधमारी होने लगी। जिस तरह समान विचारधारा वाले विपक्षी दल दूसरे दलों के नेताओं को अपने पाले में करने लगे हैं, उससे विपक्षी एकता की कोशिश फिलहाल विपक्ष बनाम विपक्ष की सियासी जंग में बदल गई है। टीएमसी कांग्रेस नेताओं को अपने पाले में कर रही है। कांग्रेस लेफ्ट नेताओं को शामिल कर रही है। आपस में पाले बदलने का ट्रैड अभी रुकता भी नहीं दिख रहा है। इससे दलों के बीच कटूता भी सामने आई है। जहां महज कुछ दिनों पहले विपक्षी एकता के लंबे-चौड़े दावे हो रहे थे, अब बयानों में तल्खी है। अब तो सवाल यह पूछा जा रहा है कि विपक्ष बनाम विपक्ष की जंग कहां तक जाएगी

एकता की बातों के बीच ऐसी नौबत क्यों आई क्षेत्रीय दल विपक्षी एकता में जारी इस जंग के लिए कांग्रेस को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उनका मानना है कि पिछले कुछ सालों से कांग्रेस के गिरते ग्राफ से हालात बदल गए हैं, जिसे कांग्रेस समझ नहीं पा रही है। क्षेत्रीय दल कांग्रेस की निष्क्रियता को जिम्मेदार ठहराते हैं। उनका मानना है कि कई

बुजूर्गों में सेहत समस्याएं और अन्य चुनौतियाँ

डॉ अश्वनी कुमार मल्होत्रा

कुछ दिन पहले मेरे मित्र ने व्हाट्सएप पर अपनी माता जी के 96 वे जन्म दिन की कुछ तस्वीरें भेजी। मैंने अपने मित्र को फोन कर के बधाई दी और कहा कि मैं और मेरी पतनी उनसे मिलने और उनका आशीर्वाद लेने एक दिन जरूरआएंगे। जब हम उनसे मिले तो उनके मुख पर तेज और मुस्कान देख कर मन बहुत प्रसन्न हुआ इधर उधर कि बाते करते हुए जब मैंने उनसे उनकी सेहत का राज़ पुछा तो उन्होंने कहा, इन्हें बेटा मैं ने सदा सादा जीवन जिया है और संयुक्त परिवार में रही हूँ, जहाँ मुझे हमेशा प्यार ही मिला है। कुलदीप (मैरे मित्र कि और इशारा कर) के पिता की एक एक्सीडेंट में मौत के बाद, उसने, उसकी पतनी और उसके बच्चों ने मेरा ध्यान रखा है और मुझे यह कभी अहसास नहीं होने दिया कि मैं अकेली हूँ। उनके मुख से ये शब्द सुनकर मैंने उन बजुर्गीं की बात याद आ गई जो अपनी पतनी की मौत, बच्चों के विदेश में बस जाने के

बाद, बच्चों द्वारा जायदाद धोखे से अपने नाम कराने और प्रताड़ित होने

**क्या हेल्थ कार्ड हमारी जिंदगी बदल पाएगा जाने
कैसे इलाज के तरीके का हो जाएगा कायापलट**

देवी शेष्टी

अगर अमेरिका के किसी अस्पताल में एक रात 200 मरीज भर्ती होते हैं तो उनमें से एक की मौत हो सकती है। लापरवाही के चलते नहीं, इलाज में मँगड़ी की वजह से। अमेरिकी अस्पतालों को दुनिया में सबसे सुरक्षित माना जाता है, इसके बावजूद वहाँ उनमें भर्ती होने में स्कार्फ़ डाइविंग के मुकाबले दस गुना ज्यादा जोखिम है। हमें अस्पतालों को मरीजों के लिए एक सुरक्षित स्थान बनाने की ज़रूरत है। जब हम अपने किसी करीबी को अस्पताल में भर्ती कराते हैं तो क्यों बार-बार पूछताछ करते हैं कि कौन सा डॉक्टर मरीज को देखने वाला है हवाई जहाज पर चढ़ते हुए पायलट के अनुभव को लेकर कभी पूछताछ क्यों नहीं करते? इसका जवाब हेल्पिंगर सेक्टर और एविएशन इंडस्ट्री द्वारा अपनाई गई कार्य प्रक्रियाओं के अंतर में निहित है। हेल्पिंगर इंडस्ट्री के विपरीत, कोई भी पायलट टेकऑफ, लैंडिंग या क्रूजिंग की अपनी खास शैली नहीं अपना सकता। पायलटों को निर्धारित प्रोटोकॉल का पूरी सख्ती से पालन करना होता है। कॉकपिट में उनकी हर गतिविधि, एक-एक चाल, हर बातचीत रेकॉर्ड की जाती है, जो 'ब्रैकबॉक्स' में दर्ज होती रहती है। पुणे क्रैश होने की स्थिति में हर छोटे-बड़े ब्योरो को देखा, समझा और परखा जाता है। अगर हादसे के पीछे किसी तरह की मानवीय भूल का पता चले तो वह भविष्य के लिए सबक होता है। मूलतः टेक्नलॉजी और प्रोटोकॉल का जोड़ ही है, जिस पर सख्ती से अमल ही एविएशन इंडस्ट्री को दुनिया की सबसे सेफ इंडस्ट्री बनाता है।

दुर्भाग्यवश हेल्पिकेरय में इलाज के प्रोटोकॉल का पालन करना कठिन है क्योंकि भारत सहित विकासशील देशों की 90 फीसदी अस्पतालों में इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रेकॉर्ड्स (ईएमआर) की व्यवस्था नहीं है। ईएमआर के जरूरी अस्पताल के भीतर इलाज के दौरान मरीजों, मशीनों, नर्सों, टेकिन्कल कर्मचारियों और डॉक्टरों के बीच चलने वाली तमाम गतिविधियों

को मोबाइल ट्रैटफोर्म पर रियल टाइम रेकॉर्ड करते चलना आसान होता है। फिलवर्क किसी मरीज की हालत गंभीर होने पर यह पता करना बहुत मुश्किल होता है कि आखिर गड़बड़ी कहां हुई, घटनाक्रम क्या रहा, क्यों स्थितियां बिगड़नी शुरू हुई। बेडसाइड ऐपर रेकॉर्ड में डीटेल इतने कम होते हैं कि उनके विशेषण से कोई सटीक निष्कर्ष निकालना सभव नहीं होता। किसी भी काम्प्लिकेशन के कारणों की तह तक पहुंचने में असमर्थता डॉक्टरों को ही नहीं सिविल सोसाइटी को भी परेशान कर रही है। सितंबर 2018 में उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि राज्य में कोई भी डॉक्टर कागज पर दवाएं प्रिस्काइब नहीं करेगा। प्रिस्क्रिप्शन की गड़बड़ीयों से बचने के लिए उनसे कहा गया है कि वे सब डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन को अपनाएं। दुर्भाग्यवश उस आदेश पर अमल सुनिश्चित करने लायक डिजिटल टूल्स तब उपलब्ध ही नहीं थे। लेकिन आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन लॉन्च होने के बाद स्थितियां बदलने वाली हैं। अगर हम डॉक्टरों, नर्सों और टेक्निकल कर्मचारियों को कागज और पेन के बदले डिजिटल टूल्स उपलब्ध कराने लगे तो हेल्थकेयर के दौरान मरीजों की मौतों की सर्वांगी में अच्छी खासी कमी लाई जा सकती है, हेल्थकेयर सुविधाओं तक लोगों की पहुंच जर्बर्दस्त ढंग से बढ़ाई जा सकती है और इलाज में होने वाला खर्च भी काफी कम किया जा सकता है। आज मरीजों के बेडसाइड ऐपर रेकॉर्ड के जरिए सटीक क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए जरूरी मेडिकल डेटा हासिल करना डॉक्टरों के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द होता है। डॉक्टर दबाव में होते हैं कि कोई ऐसी मानवीय भूल न हो जाए, जिससे मरीज की जिंदगी प्रभावित हो। डॉक्टर बिरादरी के इनपुट के सहारे अच्छी तरह तैयार किया गया ईएमआर ही मरीजों का इलाज करने का उनवा आनंद वापस लौटा सकता है। यहां सवाल उठता है कि अगर ईएमआर हेल्थकेयर का कायापलट कर सकता है तो फिर अमेरिका अस्पताल आज भी सेफ्टी के मामले में संघर्ष करते क्यों नजर आते हैं इसका कारण यह है कि अमेरिका में ईएमआर को मूलतः बिलिंग सॉफ्टवेयर के रूप में विकसित करने पर अरबों रुपये फूक दिए गए। मेडिकल फीचर्स जोड़ने का ख्याल बाद में आया। आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन भारतीय डिजिटल हेल्थ स्टार्टअप्स के लिए संभावनाओं के नए द्वारा खोलेगा। इस मिशन से जरा सा इशारा पाकर देश के तमाम अस्पताल ईएमआर की व्यवस्था कर लेंगे। एक अदाद हेल्थ आईडी पेशेंट्स के लिए अपना पूरा हेल्थ रेकॉर्ड मोबाइल में सेव रखना आसान बना देगा, जो देश के किसी भी कोने में डॉक्टरों द्वारा अपने लैपटॉप पर देखा जा सकेगा। डॉक्टर हर विजिट में पेशंट से एलर्जी, फैमिली हिस्ट्री और पास्ट मेडिकल रेकॉर्ड से जड़े वही-वही सवाल पूछना बंद कर देंगे। सिरदर्द से लेकर कैंसर तक हर मेडिकल समस्या को लेकर डॉक्टर से पहला इंटरएक्शन ऑनलाइन होगा। इंजनियर भरे हॉस्पिटल दौरों के बजाय डॉक्टरों से ऑनलाइन संपर्क निश्चित रूप से काफी सुविधाजनक होगा। ब्रूड टेस्ट, सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड- सबकी रिपोर्ट क्लाउड पर उपलब्ध होंगी, सो मरीज को बार-बार वही टेस्ट करवाने के झंझट से नहीं गुजरना पड़ेगा। जल्दी ही डेटा एनालिटिक्स ईएमआर पर क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बना देंगे, जिससे पेशंट की स्थितियों को देखते हुए वैकल्पिक डायग्नोसिस उतनी ही आसान हो जाएगी जितना कि ऑनलाइन सेकंड ऑपिनियन देना। झोला छाप डॉक्टरों से पिंड अपने आप छूट जाएगा क्योंकि सिर्फ रजिस्टर्ड डॉक्टर ही डिजिटल पैड पर प्रिस्क्रिप्शन दे सकते। डिजिटाइजेशन ने हर इंडस्ट्री का कायापलट कर दिया है। दुनिया की सबसे बड़ी टैक्सी कंपनी ऊबर के पास अपनी कोई गाड़ी नहीं है। दुनिया की सबसे लाक्रिय डिजिटल मीडिया कंपनी फेसबुक खुद कोई कर्टेंट नहीं क्रिएट करती। दुनिया की सबसे बड़ी रिटेलर कंपनी अलीबाबा के पास अपना कोई सामान नहीं होता। ऐसे ही दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थकेयर प्रोवाइडर कंपनी के पास अपना कोई बेड नहीं होगा क्योंकि वह एक हेल्थऐप होगी। हमारे टेकसैपी प्रैथानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रोत्साहन से वह हेल्थऐप भारत के प्रतिभाशाली सॉफ्टवेयर इंजीनियरों द्वारा विकसित की जाएगी। बाकी दुनिया के सामने उस यंग, स्मार्ट, इन्टर्यूटिव अपील वाले हेल्थऐप को अपनाने के सिवा और कोई विकल्प नहीं होगा।

विपक्षी एकता

नरेंद्र नाथ

पिछले कुछ महीनों से 2024 आम चुनावों में बीजेपी से मकाबले के लिए विपक्षी दलों की एकता की कोशिश चल रही थी। इसके लिए एक के बाद एक कई मीटिंग भी हुई। ऐसा संदेश गया कि विपक्षी दल पिछली गलतियों से सीख लेते हुए इस बार एक मंच पर आएंगे और आपसी मतभेद दूर करेंगे। लेकिन अभी विपक्षी एकता कोई आकार लेती कि पिछली बार की तरह ही फिर यह पटरी से उतरती दिखने लगी। हालांकि इस बार इसके पीछे कारण थोड़े अलग हैं। अभी तक विपक्षी एकता में नेतृत्व को लेकर सबसे अधिक विवाद होता था। लेकिन इस बार विपक्षी दलों की आपस में ही सेंधमारी होने लगी। जिस तरह समान विचारधारा वाले विपक्षी दल दूसरे दलों के नेताओं को अपने पाले में करने लगे हैं, उससे विपक्षी एकता की कोशिश फिलहाल विपक्ष बनाम विपक्ष की सियासी जंग में बदल गई है। टीएमसी कांग्रेस नेताओं को अपने पाले में कर रही है। कांग्रेस लेफ्ट नेताओं को शामिल कर रही है। आपस में पाले बदलने का फ्रैंड अभी रुकता भी नहीं दिख रहा है। इससे दलों के बीच कटूता भी नहीं सामने आई है। जहां महज कुछ दिनों पहले विपक्षी एकता के लंब-चौड़े दावे हो रहे थे, अब बयानों में तल्खी है। अब तो सवाल यह पूछा जा रहा है कि विपक्ष बनाम विपक्ष की जंग कहां तक जाएगी एकता की बातों के बीच ऐसी नौबत क्यों आई क्षेत्रीय दल विपक्षी एकता में जारी इस जंग के

ਕਹੀ ਖ਼ਾਲੀ ਪੁਲਾਵ ਤੋ ਨਹੀਂ

लए कांग्रेस का हा जिम्मेदार ठहरा रह है। उनका मानना है कि पछले कुछ सालों से कांग्रेस के गिरते ग्राफ से हालात बदल गए हैं, जिसे कांग्रेस समझ नहीं पा रही है। क्षेत्रीय दल कांग्रेस की निष्क्रियता को जिम्मेदार ठहराते हैं। उनका मानना है कि कई राज्यों में कांग्रेस बीजेपी को टक्कर नहीं दे रही है, ऐसे में विषय का स्पेस किसी न किसी को तो लेना ही होगा। पूर्वीतर भारत के एक क्षेत्रीय दल के सीनियर नेता ने एनबीटी को बताया कि दो सालों में अब तक पार्टी एक पूर्णकालिक अध्यक्ष ही नहीं चुन पाई है। उन्होंने कहा कि आपसी गुटबाजी अलग बात है, पार्टी धरातल पर गंभीर नहीं दिखती है। नेताओं ने कहा कि बाहर ही नहीं, बिल्कुल कांग्रेस के अंदर भी इस बात को लेकर बेचैनी है। ऐसे में अब क्षेत्रीय दलों का मानना है कि 2021 में कांग्रेस की स्थिति 2004 वाली नहीं रही और विपक्ष की ताकत का नए सिरे से गठन होना चाहिए, उन्हें स्पेस मिलना चाहिए। वहीं आम आदमी पार्टी, टीएमसी जैसे दलों को यह भी लगने लगा है कि यही भौका है जब वे अपनी पार्टी का विस्तार कर सकते हैं।

उथर कांग्रेस को लगता है कि क्षेत्रीय दल अति महत्वाकांक्षा का शिकार हो रहे हैं, और वे जो कर रहे हैं उससे आखिरकार बीजेपी को ही फायदा होगा। कांग्रेस नेताओं का तर्क है कि विपक्षी एकता का मतलब यह नहीं है कि वे अपनी जमीन बाकी दलों को दे दें। लेकिन कांग्रेस भी इस खेल में शामिल है। लेफ्ट नेता कन्हैया को तब दल में शामिल किया गया, जब सीपीआई नेता डॉ. राजा पार्टी से यह फैसला नहीं लेने का

आग्रह कर रहा था। वहा कन्हैया के शामिल होने से न सफ लेफ्ट दल से, बल्कि बिहार में आरजेडी से भी कांग्रेस के रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं। सूत्रों के अनुसार पप्पू यादव को भी कांग्रेस शामिल कर सकती है, जिनका आरजेडी से विरोध है। उसी तरह टीएमसी ने गोवा, त्रिपुरा, असम और मेघालय में कांग्रेस के कुछ सीनियर नेताओं को अपने पाले में किया, तो अभी कई नेताओं के उनके संपर्क में रहने की भी बात कही जा रही है। इन राज्यों में टीएमसी भी चुनाव में उत्तरेगी। आम आदमी पार्टी दिल्ली के अलावा उत्तराखण्ड, पंजाब, गुजरात सभी जगह कांग्रेस का स्पेस ले रही है। अभी जो संकेत मिल रहे हैं उनके हिसाब से अगले कुछ दिनों में तनातनी और भी बढ़ सकती है। इसका असर विपक्षी दलों की एकता पर पड़ सकता है। तो क्या विपक्षी एकता की कोशिश अब पूरी तरह से बेफट्टी हो जाएगी नेताओं का मानना है कि अभी यह कहना जल्दबाजी होगा। विपक्षी दलों के नेताओं के अनुसार अभी इस मसले पर तनातनी जरूर दिख सकती है, लेकिन इसका असर विपक्षी एकता पर नहीं दिखेगा। उन्होंने कहा कि हर पार्टी अपने संगठन को मजबूत करना चाहती है, उसका विस्तार करना चाहती है। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन 2024 में बीजेपी के सामने इनके लिए एक होने का विकल्प नहीं होगा, बल्कि यह सबकी मजबूरी होगी। ऐसे में वे कुछ महीनों तक खुद को विस्तार देकर एक बार फिर विपक्षी एकता की कोशिश में लग सकते हैं। वहीं अगले साल फरवरी-मार्च में पांच राज्यों के चुनाव परिणाम भी कोई न कोई दिशा तो लेंगे ही।

दक्षेस अपनी सार्थकता सिद्ध नहीं
कर पाया, अब जन-दक्षेस
बनना चाहिए

सरकारें लड़ी-झगड़ी रहें तो भी लोगों के बीच बातचीत जारी रहे। यह इसलिए जरूरी है कि दक्षिण और मध्य एशिया के 16-17 देशों के लोग एक ही आर्य परिवार के हैं। उनकी भाषा, भूषा, भोजन, भजन और भेषज अलग-अलग हो सकते हैं लेकिन उनकी संस्कृति एक ही है। दक्षेस (सार्क) के विदेश मित्रियों की जो बैठक न्यूयार्क में होने वाली थी, वह स्थिगित हो गई है। उसका कारण यह बना कि अफगान सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करेगा सच पूछा जाए तो 2014 के बाद दक्षेस का कोई शिखर सम्मेलन वास्तव में हुआ ही नहीं। 2016 में जो सम्मेलन इस्लामाबाद में होना था, उसका आठ में से छह देशों ने बहिष्कार कर दिया था, क्योंकि जम्मू में आतंकवादियों ने उन्हीं दिनों हमला कर दिया था। नेपाल अकेला उस सम्मेलन में सम्मिलित हुआ था, क्योंकि नेपाल उस समय दक्षेस का अध्यक्ष था और काठमाडौं में दक्षेस का कार्यालय भी है। दूसरे शब्दों में इस समय दक्षेस बिल्कुल पंगु हुआ पड़ा है। यह 1985 में बना था लेकिन अब 35 साल बाद भी इसकी ठोस उपलब्धियां नगण्य ही हैं, हालांकि दक्षेस-राष्ट्रों ने मुक्त व्यापार, उदार वीजा-नीति, पर्यावरण-रक्षा, शिक्षा, चिकित्सा आदि क्षेत्रों में परस्पर सहयोग पर थोड़ी बहुत प्रगति जरूर की है लेकिन हम दक्षेस की तुलना यदि यूरोपीय संघ और 'आसियान' से करें तो वह उत्साहवर्द्धक नहीं है। फिर भी दक्षेस की उपयोगिता से इंकार नहीं किया जा सकता है। इसे फिर से सक्रिय करने का भरसक प्रयत्न जरूरी है। जिन दिनों 'सार्क' यानि 'साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन' नामक संगठन का निर्माण हो रहा था तो इसका हिंदी नाम 'दक्षेस' मैंने दिया था। 'नवभारत टाइम्स' के एक संपादकीय में मैंने 'दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ' का संक्षिप्त नाम 'दक्षेस' बनाया था। उस समय यानि अब से लगभग 40 साल पहले भी मेरी राय थी कि दक्षेस के साथ-साथ एक

लगभग 40 साल पहले मी भरा राय था कि दक्षेस के साथ-साथ एक जन-दक्षेस संगठन भी बनना चाहिए यानि सभी पड़ोसी देशों के समान विचारों वाले लोगों का संगठन होना भी बहुत जरूरी है। सरकारें आपस में लड़ती-झगड़ती रहें तो भी उनके लोगों के बीच बातचीत जारी रहे। यह इसलिए जरूरी है कि दक्षिण और मध्य एशिया के 16-17 देशों के लोग एक ही आर्य परिवार के हैं। उनकी भाषा, भूषा, भोजन, भजन और भेषज अलग-अलग हो सकते हैं लेकिन उनकी संस्कृति एक ही है। आराकान (म्यांमार) से खुरासान (ईरान) और त्रिविष्टुप (तिब्बत) से मालदीव के इस प्रदेश में खनिज संपदा के असीम भंडार भरे हुए हैं। यदि भारत चाहे तो इन सारे पड़ोसी देशों को कुछ ही वर्षों में मालामाल किया जा सकता है और करोड़ों नए रोजगार पैदा किए जा सकते हैं। यदि हमारे ये देश यूरोपीय राष्ट्रों की तरह संपन्न हो गए तो उनमें स्थिरता ही नहीं आ जाएगी बल्कि यूरोप के राष्ट्रों की तरह वे युद्धमुक्त भी हो जाएंगे। पिछले 50-55 वर्षों में लगभग इन सभी राष्ट्रों में मुझे दर्जनों बार जाने और रहने का अवसर मिला है। भारत के लिए उनकी सरकारों का रवैया जब-तब जो भी रहा हो, जहां तक इन देशों की जनता का सवाल है, भारत के प्रति उनका रवैया मैत्रीपूर्ण रहा है। इसीलिए भारत के प्रबुद्ध और संपन्न नागरिकों को जन-दक्षेस के गठन की पहल तुरंत करनी चाहिए। वह दक्षेस के नहले पर ढहला सिद्ध होगा।

